

मुकदमों का विवरण

संजय पांडुरंग कालेटे बनाम.

विस्ट्रा आई. टी. सी. एल. (इंडिया) लिमिटेड और अन्य (2023 की सिविल अपील Nos.7467-7468)

04 दिसंबर, 2023

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:क्या एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष दायर की गई अपील सीमा के भीतर थी। अपने विवादित आदेश में, एन. सी. एल. ए. टी. ने निष्कर्ष निकाला कि अपील को इस आधार पर सीमित किया गया था कि इसे दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 61 के तहत 45 दिनों की बाहरी सीमा से परे स्थापित किया गया था।

दिवाला और दिवालियापन संहिता **2016** -एस. **61**-अपीलार्थी एफ. आई. ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक अंतर्वर्ती आवेदन का नेतृत्व किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एस.7 निगमित देनदार की ओर से आवेदन का नेतृत्व प्रत्यर्थी नं.2 निदेशक मंडल के प्राधिकरण या अपीलार्थी को सूचित किए बिना-एन. सी. एल. टी. ने आवेदन पर सुनवाई की-एन. सी. एल. टी. का आदेश घोषित नहीं किया गया था-आदेश एन. सी. एल. टी. की रजिस्ट्री द्वारा एन. सी. एल. टी. द्वारा एन. सी. एल. टी. की रजिस्ट्री द्वारा एन. सी. एल. टी. द्वारा एन. सी. एल. टी. द्वारा एन. सी. एल. टी. द्वारा दायर किया गया था, हालांकि आदेश में एन. सी. एल. टी. द्वारा खारिज किए गए अपीलार्थी के आवेदन की तारीख है-आदेश के खिलाफ अपील एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष ई-फाई के माध्यम से की गई थी-एन. सी. एल. ए. टी. ने आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित बताते हुए खारिज कर दिया-स्वामित्व:

आयोजित किया गया:तत्काल मामले में, अपीलार्थी द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई 17.05.2023 (NCLT) के लिए कारण सूची इंगित करती है कि मामला प्रवेश के लिए सूचीबद्ध किया गया था न कि घोषणा के लिए-इसके अलावा, अदालत के एक विशिष्ट प्रश्न पर, यह अपीलार्थी और प्रतिवादी के वकील के बीच विवाद में नहीं है, कि NCLT द्वारा 17.05.2023 पर कोई ठोस आदेश पारित नहीं किया गया था-इन परिस्थितियों में, सीमा 17.05.2023 पर चलना शुरू नहीं होगी, जिस तारीख को सुनवाई समाप्त हुई थी-क्योंकि 30.05.2023 से पहले कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, इसलिए अपीलार्थी के लिए आवेदन 314 दर्ज करने का कोई अवसर नहीं था।

17.05.2023 पर एक प्रमाणित संपादित प्रति के लिए-फ़िंग के लिए समय एक अपील केवल तभी शुरू होगी जब अपील किए गए आदेश को अपलोड किया गया था क्योंकि उस तारीख से पहले कोई आदेश घोषित नहीं किया गया था-सीमा की अवधि 30.05.2023 पर चलने लगी थी-s में प्रदान की गई 30 दिन की सीमा अवधि। 61(2) आई. बी. सी. ने 29.06.2023 पर निष्कर्ष निकाला-हालाँकि अपील तीस दिनों की अवधि से आगे की गई थी, लेकिन यह पंद्रह दिनों की क्षम्य अवधि के भीतर थी-इस न्यायालय का विचार है कि अपील को एन. सी. एल. ए. टी. को इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए बहाल किया जाना चाहिए कि क्या अपीलार्थी ने तीस दिनों से अधिक की देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया है-इसलिए, देरी को माफ करने से इनकार करने वाले एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और कार्यवाही को एन. सी. एल. ए. टी. के लिए बहाल कर दिया जाता है। [पैरा 19 और 21]

सीमा-क्या सीमा को चलने से रोकता है, अपील की ई-फाई लिंग की तारीख या अपील की भौतिक प्रतिलिपि:

आयोजित किया गया: संकेत अग्रवाल मामले में यह तय किया गया था कि अपील की ई-फाई लिंग की तारीख और अपील की भौतिक प्रति की फाई लिंग नहीं, सीमा को चलने से रोकती है। [पैरा 22]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

वी. नागराजन बनाम एस. के. एस. इस्पात (2022) 2 एस. सी. सी. 244-लागू नहीं हुआ।

संकेत कुमार अग्रवाल बनाम एपीजी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड 2023 एससीसी

ऑनलाइन एससी 976-पर भरोसा किया गया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: 2023 की सिविल अपील Nos. 7467-7468।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के 2023 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) और 2023 की आई. ए. <आई. डी. 3 में दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

श्याम दीवान, नकुल दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता।, संदीप एस. सालुंखे, सत्यजीत ए. देसाई, अमित के. पाठक, किरण शिंदे, सिद्धार्थ गौतम, अभिनव के. मुत्यालवार, गजानन एन. तीर्थकर, विजय राज सिंह चौहान, सुश्री अनघा एस. देसाई, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, समीर मलिक, वरुण कालरा, महिप सिंह, फरहा मलिक, मेसर्स डी. एस. के. लीगल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

1. स्वीकार करें।

2. ये अपीलें राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के 14 सितंबर 2023 के एक फैसले से दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 1 की धारा 62 के तहत आती हैं।² एन. सी. एल. ए. टी. ने सीमा के आधार पर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, मुंबई 3 के आदेश के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया।

3. शुरुआत में, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय के निर्णय सीमा के प्रश्न के निर्धारण तक सीमित हैं। निर्णय में पक्षों के बीच बड़े विवाद के गुण-दोष पर विस्तृत तथ्यों और कथनों का विश्लेषण नहीं किया जाता है।

4. संक्षेप में, प्रतिवादी 1, विस्त्रा आई. टी. सी. एल. (इंडिया) लिमिटेड ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें कॉर्पोरेट देनदार एविरेंट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 4 शुरू करने की मांग की गई। अपीलार्थी निगमित ऋणदाता का एक पूर्व निदेशक है, जो आरोप लगाता है कि प्रत्यर्थी 1 के नेतृत्व में धारा 7 आवेदन विभिन्न उत्तरदाताओं के साथ मिलीभगत पर आधारित है, जिसमें प्रत्यर्थी 2 और प्रत्यर्थी 3 शामिल हैं, जो निगमित ऋणदाता के पूर्व निदेशक हैं। अपीलार्थी ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक अंतर्वर्ती आवेदन का नेतृत्व किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया कि निगमित ऋणदाता की ओर से धारा 7 के आवेदन का जवाब निदेशक मंडल के प्राधिकरण या अपीलार्थी को सूचित किए बिना प्रत्यर्थी 2 के नेतृत्व में दिया गया था।

1 "आईबीसी "

2 "एन. सी. एल. ए. टी. "3" एन. सी. एल. टी "4" सी. आई. आर. पी. ".

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

5. 17 मई 2023 को एन. सी. एल. टी. ने अपीलार्थी के नेतृत्व में आवेदन पर सुनवाई की। प्रस्तुतियों से और न्यायालय के एक विशिष्ट प्रश्न पर, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी और प्रतिवादी के वकील के बीच यह विवाद नहीं है कि 17 मई 2023 को एन. सी. एल. टी. का आदेश नहीं सुनाया गया था और कोई ठोस आदेश पारित नहीं किया गया था। आदेश को एन. सी. एल. टी. की रजिस्ट्री द्वारा 30 मई 2023 को अपलोड किया गया था, हालांकि आदेश की तारीख 17 मई 2023 है। आदेश द्वारा,

एन. सी. एल. टी. ने अपीलार्थी के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आवेदन कॉर्पोरेट ऋणदाता के निदेशक मंडल से प्राधिकरण के बिना किया गया था और धारा 7 आवेदन में कार्यवाही में देरी करने के लिए प्रथम दृष्टया तुच्छ था। अपीलार्थी ने 30 मई 2023 को एक प्रमाण पत्र संपादित प्रति के लिए आवेदन किया, जो 1 जून 2023 को प्राप्त हुआ था। आदेश के खिलाफ अपील 10 जुलाई 2023 को एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष ई-फाई के माध्यम से की गई थी।

6. अपीलार्थी ने अपील के साथ देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन का नेतृत्व किया। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि (i) अपीलार्थी को आदेश की सामग्री के बारे में केवल 30 मई 2023 को पता चला और सीमा अवधि इस तारीख से चलनी चाहिए; (ii) एन. सी. एल. ए. टी. को 05 जून 2023 और 02 जुलाई 2023 के बीच गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद कर दिया गया था और इस अवधि को सीमा की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए।

7. उपरोक्त घटनाओं की पृष्ठभूमि में, एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या अपील सीमा के भीतर की गई थी। अपने विवादित आदेश में, एन. सी. एल. ए. टी. ने निष्कर्ष निकाला कि अपील को इस आधार पर सीमित किया गया था कि इसे आई. बी. सी. की धारा 61 के तहत 45 दिनों की बाहरी सीमा से परे स्थापित किया गया था। एन. सी. एल. ए. टी. ने वी. नागराजन बनाम एस. के. एस. इस्पात 5 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि समय 30 मई 2023 से शुरू होना चाहिए-अपलोड की तारीख। चूंकि सीमा अवधि 17 मई 2023 को शुरू हुई थी, इसलिए 10 जुलाई 2023 को अपील का आवेदन आई. बी. सी. के तहत निर्धारित 45 दिनों की बाहरी सीमा से परे माना गया था। इसके अलावा, एन. सी. एल. ए. टी. ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि 05 जून 2023 से 02 जुलाई 2023 तक की वार्षिक ग्रीष्मकालीन छुट्टियों को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि एन. सी. एल. ए. टी. ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा गया था कि रजिस्ट्री खुली रहेगी और छुट्टियों के दौरान अपील की अनुमति होगी। तदनुसार, अपील को सीमा द्वारा वर्जित बताते हुए खारिज कर दिया गया था।

5 (2022) 2 एससीसी 244 317

संजय पांडुरंग कालेटे बनाम विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 318

8. अलग से, यह ध्यान दिया जा सकता है कि 19 मई 2023 को, एन. सी. एल. टी. ने प्रतिवादी 1 के धारा 7 आवेदन की अनुमति दी और कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की। आदेश के खिलाफ अपीलार्थी की अपील को एन. सी. एल. ए. टी. ने 05 अक्टूबर 2023 को खारिज कर दिया है।

9. नीचे दी गई तालिका प्रासंगिक तिथियों को दर्शाती है:

तिथि	आयोजन
17.05.2023	अपीलार्थी के अंतर्वर्ती आवेदन

	की सुनवाई एन. सी. एल. टी. द्वारा की गई। लेकिन, कोई आदेश जारी नहीं किया गया।
30.05.2023	उपरोक्त अंतर्वर्ती आवेदन को खारिज करने का आदेश एन. सी. एल. टी. की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। हालांकि, आदेश में 17.05.2023 (सुनवाई की तारीख) की तारीख है।
30.05.2023	अपीलार्थी ने एन. सी. एल. टी. आदेश की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन किया।
01.06.2023	अपीलार्थी को एन. सी. एल. टी. आदेश की एक प्रमाणित प्रत प्राप्त हुई।
29.06.2023	30-एन. सी. एल. टी. आदेश अपलोड करने की तारीख से दिन।
10.07.2023	अपीलार्थी ई-फाई ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील का नेतृत्व किया।

10. एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष एन. सी. एल. टी. के आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार आई. बी. सी. की धारा 61 से उत्पन्न होता है, जो निम्नलिखित शर्तों में है:

“61. अपील और अपीलीय प्राधिकरण-(1) किसी भी चीज के बावजूद

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निहित इसके विपरीत, इस भाग के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में

अपील कर सकता है।(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अपील राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष तीस दिनों के भीतर की जाएगी:

बशर्ते कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील करने की अनुमति दे सकता है यदि यह संतुष्ट होता है कि अपील नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था, लेकिन ऐसी अवधि पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होगी।”

धारा 61 (2) में तीस दिनों की सीमा अवधि का प्रावधान है।धारा के परंतुक में प्रावधान है कि एन. सी. एल. ए. टी. तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद अपील करने की अनुमति दे सकता है यदि यह संतुष्ट किया जाता है कि अपील नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था, लेकिन ऐसी अवधि पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होगी।इसलिए, 45 दिन बाहरी सीमा है जिसके भीतर एन. सी. एल. टी. के आदेश से एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

11. ऊपर पैराग्राफ 9 में तारीखों की तालिका इंगित करती है कि दो संभावित परिदृश्य हैं।यदि यह न्यायालय मानता है कि सीमा 30 मई 2023 से शुरू होती है, तो अपील की ई-फाई लिंग की तारीख 15 दिनों की क्षम्य अवधि के भीतर आएगी।वैकल्पिक रूप से, यदि सीमा 17 मई 2023 से शुरू होती है, तो अपील की ई-फाई लिंग की तारीख 45 दिनों की बाहरी सीमा से अधिक है और इसे माफ नहीं किया जा सकता है।

12. अपने विवादित आदेश में, एन. सी. एल. टी. ने सीमा के आधार पर अपील को खारिज करने के वी. नागराजन (ऊपर) के फैसले पर भरोसा किया है।अपीलार्थी ने तथ्यों और कानून दोनों पर वर्तमान मामले को वी. नागराजन (उपरोक्त) से अलग करने की मांग की है और संकेत में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है।

कुमार अग्रवाल बनाम एपीजी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड 6.इसलिए यह होगा कि

आई. बी. सी. के तहत एन. सी. एल. टी. के आदेश के खिलाफ अपील के लिए लागू सीमा अवधि पर कानून को स्पष्ट करना हमारे लिए उचित होगा।

13. वी. नागराजन (ऊपर) में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उल्लेख किया कि कंपनी अधिनियम की धारा 421 (3) और आई. बी. सी. की धारा 61 (2) के बीच महत्वपूर्ण अंतर उन शब्दों का अभाव है जो "उस तारीख से न्यायाधिकरण के आदेश की एक प्रति पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती है"।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सीमा घोषणा की तारीख से शुरू होती है न कि आदेश अपलोड करने या प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त करने की तारीख से।हालाँकि, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगने वाले समय को सीमा की अवधि की गणना से बाहर रखा जाएगा, बशर्ते कि अपीलकर्ता आई. बी. सी. की धारा 61 (2) के तहत सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर लागू होता है।

14. मामले के तथ्यों पर, अदालत ने नोट किया कि अपील को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था क्योंकि अपीलार्थी ने एक प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करने का भी प्रयास नहीं किया था और केवल वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने की तारीख पर भरोसा किया था। विशेष रूप से, मामले में, आदेश पर उल्लिखित तिथि पर एक घोषणा थी और अपीलार्थी ने खुली अदालत में आदेश सुनाए जाने पर एन. सी. एल. टी. के समक्ष अपनी उपस्थिति पर विवाद नहीं किया था। हम में से एक के माध्यम से बोलते हुए (डी. वाई. चंद्रचूड़, जे), न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“33. निर्णय की धारा सी में निर्धारित दो मुद्दों का उत्तर-(i) सीमा की गणना करने के लिए समय कब लगेगा?

6 2023 एस. सी. ऑनलाइन एस. सी. 976 319

संजय पांडुरंग कालेटे बनाम विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 320 आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के लिए चलने वाली अवधि; और (ii) आई. बी. सी. के तहत पारित आदेश के खिलाफ एन. सी. एल. ए. टी. को अपील करने के लिए अनिवार्य रूप से एक प्रमाणित संपादित प्रति का विलय-लागू कानूनी व्यवस्था की एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या पर आधारित होना चाहिए, यह देखते हुए कि आई. बी. सी. अपने आप में एक संहिता है और इसका प्रभाव प्रभावी है। आई. बी. सी. की धारा 61 (1) और (2) कंपनी अधिनियम की धारा 421 (3) के विपरीत, "पीड़ित पक्ष को आदेश उपलब्ध कराने" से गणना की जाने वाली सीमा की आवश्यकता को जानबूझकर हटा देती है। आई. बी. सी. की विशेष प्रकृति के कारण, पीड़ित पक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह उचित परिश्रम करे और एन. सी. एल. ए. टी. नियमों के नियम 22 (2) की आवश्यकताओं के अनुरूप, उस आदेश की घोषणा पर एक प्रमाण पत्र की प्रति के लिए आवेदन करे जिस पर वह हमला करना चाहता है। सीमा अधिनियम की धारा 12 (2) उस डिक्री या आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को हटाने की अनुमति देती है जिसके खिलाफ अपील की जाती है। आई. बी. सी. के तहत एक आदेश से पीड़ित व्यक्ति के लिए यह खुला नहीं है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 420 (3) के तहत एन. सी. एल. टी. नियमों के नियम 50 के साथ पढ़ने और सीमा को चलने से रोकने के लिए मुफ्त प्रमाण पत्र की प्रति की प्राप्ति की प्रतीक्षा करे। इस तरह के निर्माण को स्वीकार करने से आई. बी. सी. की समयबद्ध रूपरेखा बिगड़ जाएगी। वादी को तीस दिनों के भीतर अपनी अपील दायर करनी होती है, जिसे पर्याप्त कारण दिखाने पर पंद्रह दिनों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, और इससे अधिक नहीं। प्रक्रियात्मक नियमों की व्याख्या का उपयोग किसी ऐसे कानून के मूल उद्देश्य को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है जिसका किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।

35. अपीलार्थी एन. सी. एल. टी. के समक्ष <आई. डी. 1 पर उपस्थित था जब अंतरिम राहत से इनकार कर दिया गया था और विविध आवेदन खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपनी ओर से कोई प्रभाव नहीं दिखाया है और वेबसाइट पर आदेश (12-3-2020) अपलोड करने की तारीख पर भरोसा किया है। एन. सी. एल. टी. दिनांक 31-12-2019 के आदेश के खिलाफ धारा 61 (1) के तहत एक अपील दायर करने के लिए सीमा

की अवधि धारा 61 (2) के तहत निर्धारित तीस दिन की अवधि को देखते हुए 30-1-2020 पर समाप्त हो गई। धारा 61 (2) के परंतुक के तहत निर्धारित पंद्रह दिनों की बाहरी सीमा को देखते हुए देरी की माफी के लिए कोई भी गुंजाइश 14-2-2020 पर समाप्त हो गई। कोविड-19 महामारी के कारण 23-3-2020 से लॉकडाउन और इस न्यायालय के स्वतः संज्ञान आदेश का अपीलार्थी के इस कार्यवाही में अपील करने के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और NCLAT ने

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

सीमा पर अपील को सही ढंग से खारिज कर दिया। तदनुसार, धारा 62 आई. बी. सी. के तहत वर्तमान अपील खारिज कर दी जाती है।”

15. इसके बाद, संकेत अग्रवाल (ऊपर) में, इस न्यायालय ने वी. नागराजन में निर्धारित कानून को स्पष्ट किया और कहा कि (i) सीमा एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील के ई-फाई लिंग पर चलना बंद कर देती है और भौतिक प्रति प्रस्तुत करने पर नहीं; (ii) जिस तारीख को आदेश सुनाया जाता है, उसे सीमा की गणना से बाहर रखा जाना है, और (iii) एन. सी. एल. टी. द्वारा अपीलकर्ता को प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रदान करने के लिए लिए गए समय को सीमा की गणना से बाहर रखा जाएगा, बशर्ते कि अपीलकर्ता आई. बी. सी. की धारा 61 (2) के तहत सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर लागू होता है। न्यायालय ने कहा:

“28. वर्तमान मामले में, धारा 61 (2) में निर्दिष्ट 30 दिनों की सीमा के भीतर, एक प्रमाण पत्र की संशोधित प्रति के लिए आवेदन 2 सितंबर 2022 को दिल्ली से चेन्नई भेजा गया था, जो 5 सितंबर 2022 को प्राप्त हुआ था। यह पहलू उन तथ्यों के विपरीत है जो उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष वी. नागराजन (उपरोक्त) के फैसले में प्राप्त किए थे, जहां प्रमाण पत्र की संशोधित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन भी नहीं किया गया था। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने उचित परिश्रम किया और एन. सी. एल. टी. नियम 2016 के नियम 22 (2) के संदर्भ में आदेश की घोषणा पर एक प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि के लिए आवेदन किया। प्रमाण पत्र की संपादित प्रति अपीलार्थी को 15 सितंबर 2022 को प्रदान की गई थी। इसलिए, आई. बी. सी. की धारा 61 (2) के तहत सीमा की अवधि का निर्धारण करते समय अदालत द्वारा आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करने के लिए 5 सितंबर 2022 और 15 सितंबर 2022 के बीच की 10 दिनों की अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए। 29. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एन. सी. एल. ए. टी. ने सीमा के आधार पर अपील को खारिज करने में गलती की थी।”

16. कानून की उपरोक्त चर्चा से, यह स्पष्ट है कि जिस तारीख को सीमा शुरू होती है, वह स्वाभाविक रूप से घोषणा की तारीख से जुड़ी होती है। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों में जो सवाल उठता है, वह यह है कि आदेश कब सुनाया जाता है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, 2016 7 इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करता है। नियम

संजय पांडुरंग कालेटे बनाम विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 322

89(1) एन. सी. एल. टी. नियमों के अनुसार जब एन. सी. एल. ए. टी. रजिस्ट्री अपनी कारण सूची प्रकाशित करती है, तो आदेशों की घोषणा के लिए सूचीबद्ध मामलों और अन्य मामलों के बीच अंतर किया जाता है। इसमें इस प्रकार कहा गया है:

“89. दैनिक कारण सूची तैयार करना और प्रकाशित करना।— (1) द.

रजिस्ट्री प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्य के घंटे बंद होने से पहले रजिस्ट्री के नोटिस बोर्ड पर अगले कार्य दिवस के लिए कारण सूची तैयार करेगी और प्रकाशित करेगी और राष्ट्रपति के निर्देशों के अधीन, दैनिक कारण सूची में मामलों की सूची प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में होगी, जब तक कि संबंधित पीठ द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाए; अर्थात्; -

(क) आदेशों की घोषणा के लिए मामले;

(ख) स्पष्टीकरण के लिए मामले;

(ग) प्रवेश के लिए मामले;

(घ) आदेश या निर्देशों के लिए मामले;

(ई) आंशिक सुनवाई वाले मामले, नवीनतम आंशिक सुनवाई वाले मामले जिन्हें प्राथमिकता दी गई है; और

(च) संख्यात्मक आदेश के अनुसार या पीठ द्वारा निर्देशित मामले; (जोर दिया गया) 17. इसके अलावा, एन. सी. एल. ए. टी. नियमों का भाग XIX 'मामलों के निपटान और आदेशों की घोषणा' को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित नियम प्रासंगिक हैं: “146. मामलों का निपटान।- एक आवेदन, याचिका, अपील आदि की प्राप्ति पर, न्यायाधिकरण, पक्षों को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद, उस पर ऐसे आदेश पारित करता है जो वह मानता है:

बशर्ते कि न्यायाधिकरण, किसी अपील पर विचार करने के बाद, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए उसे संक्षेप में खारिज कर सकता है, यदि न्यायाधिकरण की राय है कि उसके साथ कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। 150. आदेश की घोषणा।- (1) न्यायाधिकरण ने सुनवाई के बाद आवेदक और प्रत्यर्थी, या तो आदेश देंगे और उसका उच्चारण करेंगे।

एक बार में या उसके बाद जितनी जल्दी हो सके, लेकिन अंतिम सुनवाई के तीस दिनों के बाद नहीं।

(2) न्यायाधिकरण का प्रत्येक आदेश लिखित रूप में होगा और राष्ट्रपति या सदस्य या उस पीठ का गठन करने वाले सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा जिसने मामले की सुनवाई की और आदेश सुनाया।

(3) न्यायाधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रमाणित प्रति पक्षों को दी जाएगी।

(4) न्यायाधिकरण, आदेश के किसी भी पक्ष या स्वतः संज्ञान द्वारा किए गए आवेदन पर, प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत को अपने द्वारा किए गए आदेश को प्रेषित कर सकता है।

(5) प्रत्येक आदेश या निर्णय या सूचना पर न्यायाधिकरण की मुहर लगेगी।

151. न्यायपीठ के किसी एक सदस्य द्वारा आदेश की घोषणा।- (1)

न्यायपीठ का कोई भी सदस्य न्यायपीठ के लिए और उसकी ओर से आदेश सुना सकता है।

(2) जब इस नियम के तहत कोई आदेश सुनाया जाता है, तो कोर्ट मास्टर आदेश पत्र में एक नोट करेगा, कि अध्यक्ष और सदस्यों वाली पीठ का आदेश बेंच की ओर से खुली अदालत में सुनाया गया था।”

(जोर दिया गया) 18.एन. सी. एल. टी. नियम, 2016 के उपरोक्त प्रावधान अपील की 'सुनवाई' और आदेश की 'घोषणा' के बीच स्पष्ट अंतर करते हैं। नियम 150 (1) में प्रावधान है कि पक्षों को सुनने के बाद, आदेश या तो तुरंत या उसके तुरंत बाद घोषित किया जा सकता है, जैसा कि व्यवहार्य हो सकता है, लेकिन अंतिम सुनवाई के तीस दिनों के बाद नहीं। इसके अलावा, नियम 151 इंगित करता है कि पीठ का कोई सदस्य पीठ के लिए और उसकी ओर से आदेश सुना सकता है। जब आदेश सुनाया जाता है, तो कोर्ट मास्टर उस प्रभाव के लिए ऑर्डर शीट में एक नोट बनाएगा। उपरोक्त नियमों की भाषा इंगित करती है कि आदेश का उच्चारण आवश्यक है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है।

19. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई 17 मई 2023 की कारण सूची इंगित करती है कि मामला स्वीकार करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था न कि घोषणा के लिए। इसके अलावा, न्यायालय के एक विशिष्ट प्रश्न पर, अपीलार्थी और प्रतिवादी के वकील के बीच यह विवाद नहीं है कि एन. सी. एल. टी. द्वारा 17 मई 2023 को कोई ठोस आदेश पारित नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों में, सीमा 17 मई 2023 को शुरू नहीं होगी, जिस तारीख को सुनवाई समाप्त हुई थी। चूंकि 30 मई 2023 से पहले कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, इसलिए अपीलार्थी के लिए 17 मई 2023 को प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि के लिए आवेदन दर्ज करने का कोई अवसर नहीं था। फिलिंग के लिए अपील का समय केवल 323 से शुरू होगा।

संजय पांडुरंग कालेटे बनाम विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 324
जब अपील किया गया आदेश उस तारीख से पहले से अपलोड किया गया था
आदेश जारी किया गया।

20. वी. नागराजन (ऊपर) में, आदेश को अपलोड करने से पहले आदेश की एक स्पष्ट घोषणा की गई थी और इस प्रकार, निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, आदेश को अपलोड करने की तारीख घोषणा की तारीख के समान है। इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए, ऐसे मामलों में जहां मामले की सुनवाई किसी विशेष दिन की गई है, लेकिन आदेश बाद की तारीख में सुनाया जाता है, एन. सी. एल. टी. को आदेश पर सुनवाई की तारीख को लागू करने से बचना चाहिए। इस तरह का दृष्टिकोण एन. सी. एल. टी. नियमों का उल्लंघन होगा, जो सुनवाई और घोषणा के बीच अंतर पैदा करते हैं और एन. सी. एल. टी. को घोषणा की आवश्यकता को समाप्त करने की अनुमति नहीं देते हैं।

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सीमा की अवधि 30 मई 2023 को शुरू हुई। आई. बी. सी. की धारा 61 (2) में प्रदान की गई 30-दिवसीय सीमा अवधि 29 जून 2023 को समाप्त हुई। हालांकि अपील तीस दिनों की अवधि से आगे की गई थी, लेकिन यह पंद्रह दिनों की क्षम्य अवधि के भीतर थी। हमारा विचार है कि अपील को एन. सी. एल. ए. टी. को इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए बहाल किया जाना चाहिए कि क्या अपीलार्थी ने तीस दिनों से अधिक की देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, देरी को माफ करने से इनकार करने वाले एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित आदेश को दरकिनारा कर दिया जाता है और कार्यवाही को एन. सी. एल. ए. टी. के अधिकार क्षेत्र में बहाल कर दिया जाता है। हम इस स्तर पर सी. आई. आर. पी. बने रहने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, एन. सी. एल. ए. टी. को अपील का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया गया है।

22. समापन से पहले, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संकेत अग्रवाल (ऊपर) में यह तय किया गया था कि अपील की भौतिक प्रति की भाषा नहीं, बल्कि अपील की ई-फाई भाषा की तारीख सीमा को चलने से रोकती है। हममें से एक (डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.) के पास यह देखने का अवसर था कि ई-फाई लिंग की आवश्यकता के बाद भौतिक फाई लिंग के परिणामस्वरूप ई. एफ. ओ. आर. टी. का दोहराव होता है और यह ई-फाई लिंग के लिए एक हतोत्साहित करने वाला है। न्यायालय ने कहा कि:

“30. [...] इसके अलावा, यह पूरी तरह से समझ में नहीं आता है कि एन. सी. एल. ए. टी. को ई-फाई लिंग के अलावा भौतिक फाई लिंग पर जोर क्यों देना चाहिए। यह अनावश्यक रूप से वादियों और बार पर बोझ डालता है और ई-फाई लिंग के लिए एक हतोत्साहित करने वाला है। एक वकील या वादी जिसे ई-फाई आधारित दस्तावेजों के अलावा भौतिक प्रतियां लेने के लिए मजबूर किया जाता है, उसके पास ई-फाई लिंग का सहारा लेने का कोई ठोस कारण नहीं होगा। ई. एफ. ओ. आर. टी. का यह दोहराव समय लेने वाला है। इससे खर्च बढ़ जाता है। यह.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

यह अपने पीछे एक कार्बन पदचिह्न छोड़ता है जो इफ एस के लिए एक कठिन पंथ है। न्यायिक प्रक्रिया पारंपरिक रूप से कागजों से चलती रही है। यह मॉडल पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। यदि कुछ न्यायाधीश ई-फाई लेस से असहज हैं, तो इसका जवाब उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना है और काम करने के पुराने और पुराने तरीकों को जारी रखना नहीं है। न्यायपालिका को आधुनिक बनाना होगा और प्रौद्योगिकी के अनुकूल होना होगा। न्यायाधिकरण कोई अपवाद नहीं हो सकते हैं। यह अब विकल्प का विषय नहीं हो सकता है। आई. बी. सी. आर्थिक सुधारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसने दिवाला और दिवालियापन से संबंधित कानून को मौलिक रूप से नया रूप दिया है। जिस तरह से कानून को प्रशासित किया जाता है, उसे प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बिठाना होगा। केंद्र सरकार और न्यायाधिकरणों के प्रशासनिक प्रमुखों दोनों को अपनी नियम बनाने की क्षमता में इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करने के लिए एक निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित करना चाहिए।”

23. उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की हमें सराहना करनी चाहिए। 15 मई 2023 को, संकेत अग्रवाल (उपरोक्त) में निर्णय के तुरंत बाद, पंजीयक, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि "अपील/अंतर्वर्ती आवेदन/उत्तर/प्रत्युत्तर आदि की हार्ड प्रतियों की फ़िंग तत्काल प्रभाव वाले अधिनियम के साथ अनिवार्य नहीं होगी।" न्यायाधिकरणों द्वारा इस तरह की सक्रिय कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एक आधुनिक और प्रौद्योगिकी के अनुकूल न्यायपालिका की दिशा में कदम पूरे देश में हर न्यायिक मंच तक पहुंचे। हम एन. सी. एल. ए. टी. के अध्यक्ष, सदस्यों और रजिस्ट्री द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों की सराहना करते हैं। 24. अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

25. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों का निपटारा किया गया।

अंकित ज्ञान